

दैनिक

गाजियाबाद से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

वेल्कम इंडिया

RNI NO. UPHIN/2018/76874

नये भारत की नई सोच

वर्ष: 07 अंक: 218

मंगलवार, 18 अगस्त-2026 (गाजियाबाद)

पेज-8

मूल्य-एक रुपया

लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में भगदड़, सात श्रद्धालुओं की मौत-कई घायल

वेल्कम इंडिया, नेटवर्क

बिहार। बिहार के लखीसराय स्थित प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में सोमवार सुबह भगदड़ मच गई। इस घटना में सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोगों के घायल होने की सूचना है। हादसे के बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

मंदिर परिसर में मची अफरा-तफरी, घायलों को अस्पताल भेजा गया

बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह अशोकधाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। देखते ही देखते परिसर में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। घायल श्रद्धालुओं को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है।

एसडीपीओ ने छह मौतों की पुष्टि की

एसडीपीओ शिवम कुमार ने बताया कि घटना में सात लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा



मुख्यमंत्री सद्भाट चौधरी ने जताया दुख

बिहार के लखीसराय स्थित प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में हुए दर्दनाक हादसे में श्रद्धालुओं की मौत पर मुख्यमंत्री सद्भाट चौधरी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और पीड़ित परिवारों को इस कठिन समय में धैर्य प्रदान करने की कामना की। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल लोगों के समुचित और त्वरित इलाज के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और उपचार में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा है।



रही है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और भगदड़ जैसी स्थिति कैसे बनी, इसकी जांच की जा रही है। प्रशासन की ओर से घटना के कारणों का पता लगाने के साथ ही राहत एवं बचाव कार्य जारी है। लखीसराय के डीएम शैलेंद्र कुमार

ने अशोकधाम मंदिर में भगदड़ जैसी घटना को लेकर बताया कि प्रशासनिक टीम सुबह करीब 4:30 बजे से ही मौके पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ के बीच शाम करीब 6:30 से 6:45 बजे के बीच



मोदी ने हादसे में मारे गये लोगों के प्रति जतायी संवेदना

नयी दिल्ली, 17 अगस्त (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के लखीसराय में भगदड़ के कारण हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है। गौरतलब है कि लखीसराय में अशोक धाम मंदिर के समीप सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर आज भगदड़ मच जाने से सात महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गयी तथा 18 से अधिक लोग घायल हो गये हैं।



वे ट्रेनों के ठहराव के कारण मंदिर परिसर में भीड़ और बढ़ गई। डीएम के अनुसार, प्रशासन की ओर से पहले से ही पुलिस बल, स्वास्थ्यकर्मियों, एंबुलेंस, टोटो एंबुलेंस और वाइक एंबुलेंस समेत जरूरी व्यवस्थाएं की गई थीं। इसी दौरान करीब 6:40 से 6:45 बजे के बीच भीड़ का दबाव बढ़ने से एक तरफ की बैरिकेडिंग टूट गई। इसके बाद कुछ श्रद्धालु एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और हादसा हो गया। डीएम ने बताया कि घटना में अब तक

सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रशासन की टीम मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।

डीएम शैलेंद्र कुमार ने बताया कैसे हुआ हादसा

लखीसराय के डीएम शैलेंद्र कुमार ने अशोकधाम मंदिर में हुई भगदड़ जैसी घटना को लेकर बताया कि श्रद्धालुओं की कतार अशोकधाम हॉल्ट तक पहुंच गई थी। इसी दौरान हॉल्ट पर दो ट्रेनों भी रुकी हुई थीं। अचानक एक बिजली का पोल गिर गया। यह पोल पुरुष श्रद्धालुओं की कतार के दाहिनी ओर स्थित था। डीएम के मुताबिक, पोल गिरने के बाद मौके पर यह अफवाह फैल गई कि लोगों के ऊपर बिजली का तार गिर गया है। हालांकि, वह बिजली का तार नहीं बल्कि केबल का तार था। इस अफवाह के कारण महिलाओं की कतार में अचानक दबाव बढ़ गया और महिलाएं एक-दूसरे के ऊपर गिरने लगीं। इसी दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की टीम सुबह करीब 3 बजे से ही मौके पर निगरानी और व्यवस्था संभाल रही थी, लेकिन यह घटना अचानक हुई और महज दो मिनट के भीतर स्थिति बिगड़ गई। उन्होंने बताया कि फिलहाल अधिकारी सदर अस्पताल में मौजूद हैं और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है।

सुप्रीम को से राहुल गांधी को बड़ी राहत

आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई रोकें



वेल्कम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट ने CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह भी निर्देश दिया कि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी के खिलाफ मामले के संबंध में हाई कोर्ट के सामने कोई रिपोर्ट पेश न करें।

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने गांधी की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिबल की दलीलों पर गौर किया और कर्नाटक के रहने वाले एस. विमनेश शिशिर (जिन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था) के साथ-साथ CBI और ED को भी नोटिस जारी किए। यह बेंच इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की जांच करना चाहता है क्योंकि एक अदालत ने निर्देश जारी किए थे, जिससे जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर सवाल उठे थे। सुनवाई के दौरान, बेंच ने

प्राकृतिक न्याय के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि ऐसी कार्यवाही के दौरान अदालतों से निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। जब CBI ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की जांच करने पर आपत्ति जताई, तो बेंच ने एजेंसी के रुख पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि अगर CBI ने खुद से यह प्रक्रिया शुरू नहीं की थी और हाई कोर्ट के निर्देशों के कारण ऐसा किया था, तो सुप्रीम कोर्ट को उन हालात की जांच करने का अधिकार है। जिनमें वे निर्देश जारी किए गए थे। बेंच ने कहा कि अगर आपने इसे खुद (suo motu) शुरू नहीं किया है, तो हमें इसकी जांच करने दें। साथ ही, बेंच ने कहा कि अगर किसी एजेंसी को कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट को उस चुनौती पर सुनवाई करनी चाहिए। यह विवाद कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता एस. विमनेश शिशिर की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही कार्यवाही से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने उन आरोपों की जांच की मांग की थी जिनमें कहा गया था कि गांधी के पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं ज्यादा संपत्ति है।

'मुझे व्यवस्था से मुक्त करें!' शहजाद पूनावाला ने बीजेपी को दोबारा भेजा इस्तीफा

'सिर्फ पद छोड़ रहा हूँ, मोदी का साथ नहीं': शहजाद पूनावाला

वेल्कम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा भेजकर संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त करने का आग्रह किया है। पार्टी द्वारा शुरूआती दौर में उनका इस्तीफा खारिज किए जाने के बाद, पूनावाला ने BJP अध्यक्ष नितिन नवीन को एक नया पत्र लिखकर पद और सक्रिय सदस्यता छोड़ने के अपने फैसले को दोहराया है। नेतृत्व से आग्रह किया है कि वे इसे स्वीकार करें और उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त करें।

BJP अध्यक्ष नितिन नवीन को लिखे और पर साझा किए गए पत्र में, पूनावाला ने कहा कि वह आभारी हैं कि BJP ने शुरू में उनका इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार



करने को कहा था। हालांकि, 'लंबे और गहन चिंतन' के बाद, उन्होंने कहा कि वह पार्टी की भूमिका और सक्रिय सदस्यता से हटने के अपने फैसले पर अडिग रहने के अंतिम निर्णय पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने - जो कुछ ऐसे लोगों की वजह से हुईं जिनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है - मुझे अपने पहले के फैसले को दोहराने और उस पर

कायम रहने के लिए मजबूर किया है।' उन्होंने उन लोगों का नाम नहीं लिया। 2021 के अंत में इखद में शामिल हुए पूनावाला पार्टी के प्रमुख चेहरों और संगठन के भीतर सबसे प्रमुख मुस्लिम आवाजों में से एक बनकर उभरे थे। अपने फैसले के बारे में बताते हुए, पूनावाला ने दोहराया कि वह 'अत्यंत जरूरी वित्तीय और व्यक्तिगत परिस्थितियों' के कारण निजी क्षेत्र में जाएंगे। साथ ही, उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी और BJP के विजन और काम का समर्थन करना जारी रखेंगे - 'जहाँ भी संभव हो और जिस भी रूप में संभव हो'। पूनावाला ने कहा, 'मैं केवल 'व्यवस्था' छोड़ रहा हूँ, 'व्यक्ति' या 'विचार' नहीं।' इससे संकेत मिलता है कि पार्टी संगठन छोड़ने का उनका फैसला मोदी के प्रति उनकी राजनीतिक निष्ठा या BJP के वैचारिक ढांचे से अलग होने जैसा नहीं है।

जंगल में मुठभेड़ या कुछ और?: CM विजय के सवालोंने घिरे मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार



वेल्कम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में वन विभाग के अधिकारियों के साथ कथित मुठभेड़ में तीन लोगों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने घटना पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मारे गए तीनों लोग तमिल थे। उन्होंने कर्नाटक वन विभाग की ओर से दी गई सफाई की 'अस्वीकार्य' बताते हुए मामले की गहन जांच की मांग की है। शनिवार तड़के संदिग्ध शिकारी कथित तौर पर वन्यजीवों का शिकार करने के इरादे से जंगल में

दाखिल हुए थे। इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुरों के मुताबिक, इस दौरान संदिग्ध शिकारियों ने वन कर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में वन कर्मियों ने भी गोлияं चलाईं, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में शिकारी होने के संदेह में तीन लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। मुतकों की पहचान एंटनी स्वामी, जॉन रोज पीटर और कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

'देखिए आपके एनटीए ने क्या किया', यूजीसी-नेट में गड़बड़ी पर राहुल गांधी का पीएममोदी पर निशाना

वेल्कम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तीन विषयों की यूजीसी-नेट (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल एलिजबिलिटी टेस्ट) परीक्षा में प्रश्न पत्रों की गलतियों के चलते पुनरीक्षा कराने के फैसले को लेकर पीएम मोदी और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी पर तीखा हमला बोला है। एनटीए द्वारा अर्द्धरिश्त, कॉमर्स और सोशियोलॉजीकी परीक्षाएं कैसिल कर सितंबर में दोबारा कराने की घोषणा के बाद, राहुल गांधी ने देश की शिक्षा व्यवस्था को शोषण मशीन करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि धर्मप्र प्रधान का इस्तीफा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में पहला कदम है, आखिरी नहीं। उन्होंने कहा, कि एनटीए के नेतृत्व को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल



मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मोदी जी, देखिए आपकी NTA ने फिर क्या कर दिया है। 122 से 30 जून के बीच सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स विषय की यूजीसी-नेट परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। लगभग दो महिने बीत जाने के बाद, NTA ने इन तीनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया क्योंकि उन्होंने गलत प्रश्नपत्र तैयार किए थे और पुराने सवाल दोबारा पूछ लिए थे!"

आर-पार के मूड में छात्र: सोरेन और राहुल गांधी का पुतला फूंकने के बाद बैकफुट पर आई हेमंत सरकार

वेल्कम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित धांधली और गड़बड़ियों को लेकर सड़कों पर उतरे छात्रों का आक्रोश अब चरम पर पहुंच गया है। अंदोलन के 23वें दिन राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले फूँककर अपना उग्र विरोध दर्ज कराया। अंदोलन के बढ़ते दबाव और सड़कों पर भड़के इस गुस्से के बाद राज्य सरकार बैकफुट पर आती दिख रही है। विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासन ने

प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं को चौथे दौर की औपचारिक बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। रांची के अलावा, अन्य जिलों में भी पुतले जलाए गए और छात्रों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार और कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस ने कथित तौर पर वादा किया था कि अगर सरकार स्वतंत्रता दिवस तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो वह राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी। बाद में, राज्य सरकार ने प्रदर्शन के नेताओं को बातचीत के चौथे दौर के लिए आमंत्रित किया। यह जानकारी रांची की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त



कर रहे हैं। राज्य की राजधानी के स्टेडियम में 25 जुलाई से सैकड़ों छात्र जमा हैं। वे झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त

प्रतियोगी परीक्षा (जिसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग-संयुक्त स्नातक स्तरीय या JSSC-CGL परीक्षा के रूप में भी जाना जाता है) सहित अन्य परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की

CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC-JSSC सुधार मंच के नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि जब छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि अगर श्री सोरेन उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाते हैं या 15 अगस्त तक संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो कांग्रेस JMM के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी। हालांकि, श्री पासवान ने कहा कि 15 अगस्त के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। प्रदर्शन के नेता ने कहा, 'हमने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगर सरकार 18

अगस्त तक हमारी मांगें नहीं मानती है, तो हम 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है।' रांची सदर के सब-डिविजनल ऑफिसर कुमार रजत और लॉ एंड ऑर्डर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट धनंजय कुमार, दोनों ने शाम को विरोध कर रहे छात्रों से मिलकर सरकार के प्रस्ताव उनके सामने रखे। श्री रजत ने 'द हिंदू' को भेजे एक व्हाट्सएप मैसेज में पुष्टि की कि सरकार ने छात्रों को सोमवार (17 अगस्त, 2026) को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत के लिए बुलाया है। यह सरकार के साथ बातचीत का चौथा दौर होगा।



पुस्तकें बिकती हैं, पाटकीयता नहीं

कितना ताब छापी जा सकती है, प्रदर्शित की जा सकती है, उसका विज्ञापन किया जा सकता है, उस पर छूट दी जा सकती है और उसे बेचा जा सकता है। लेकिन पाटकीय संस्कृति केवल विपणन के माध्यम से पैदा नहीं की जा सकती। कोई पुस्तक पाठक की अलमारी तक तो पहुँच सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह उसके मन और विचारों तक भी पहुँचे। किसी पुस्तक की वास्तविक सफलता केवल उसकी बिक्री



ललित शर्मा

संपादक

करने के तरीके को बदल दिया है। अनेक युवा वीडियो, सुर्खियों और छोटी-छोटी पोस्ट को तेजी से देखने और आगे बढ़ जाने के अभ्यस्त हो रहे हैं। किसी लंबे अध्याय को पढ़ने के लिए धैर्य, एकाग्रता और मानसिक सहभागिता की आवश्यकता होती है। छोटी डिजिटल क्लिप के विपरीत पुस्तक हमेशा तत्काल मनोरंजन या उत्तेजना प्रदान नहीं करती। वह पाठक से समय और ध्यान मांगती है। यही पुस्तक बेचने और पाठक बनाने के बीच का अंतर महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी पुस्तक को सिफारिश, बेस्टसेलर के लेबल या आकर्षक विज्ञापन से प्रभावित होकर खरीद सकता है। लेकिन खरीदना केवल शुरूआत है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब पाठक पुस्तक खोलता है, उसके विचारों से जुड़ता है, उन पर विचार करता है और अगली पुस्तक पढ़ने की इच्छा विकसित करता है। एक सच्ची पाटकीय संस्कृति धीरे-धीरे विकसित होती है—जिज्ञासा, पारिवारिक वातावरण, पुस्तकालयों, विद्यालयों और पुस्तकों पर सार्थक बातचीत के माध्यम से। इस प्रक्रिया में विद्यालयों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पढ़ने को केवल परीक्षा की आवश्यकता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर कहानियाँ, जीवनीयें, विज्ञान की पुस्तकें, इतिहास, यात्रा-वृत्तांत, कविता और उनकी आयु के अनुरूप साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। जब पढ़ना केवल परीक्षा से जुड़ जाता है, तो वह बोझ जैसा लग सकता है। लेकिन जब पढ़ना खोज, आनंद और जिज्ञासा से जुड़ता है, तो यह जीवनभर की अदत बन सकता है। परिवार भी बच्चों के पुस्तक-प्रेम को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस बच्चे के माता-पिता को पढ़ते हुए देखकर बड़ बड़ा होता है, उसके लिए पुस्तक केवल पढ़ाई का साधन नहीं रहती, बल्कि ज्ञान, कल्पना और मानसिक संगति का स्रोत बन जाती है। परिवार में प्रतिदिन कुछ मिन्ट साथ बैठकर पढ़ना भी बच्चों के मन में पुस्तकों के प्रति सकारात्मक भावना पैदा कर सकता है। पुस्तकालयों को भी समय के साथ बदलना होगा। आधुनिक पुस्तकालयों का काम केवल पुस्तकों को संग्रहित करना नहीं, बल्कि पाठक तैयार करना होना चाहिए। उदात्त क्लब, लेखक से संवाद, कहानी सुनाने के कार्यक्रम, पुस्तक परिचर्चाएँ और विद्यार्थियों द्वारा पुस्तक-सिफारिश जैसी गतिविधियाँ पुस्तकालयों को जीवंत सामुदायिक केंद्र बना सकती हैं। डिजिटल संसाधन मुद्रित पुस्तकों के विकल्प के बजाय उनके सहयोगी बन सकते हैं। इसलिए चुनौती केवल अधिक पुस्तकें बेचने की नहीं है।

गरीबी बनी नासुर

उदय कशोर साह



कविता

बहुआ का मत बौध सर पे सेहरा

उतर जायेगा हँसता तेरा चेहरा

जैसे हवा में उड़ जाता है कपूर

वजूद मिट जाता है आह से हुजूर

बेबसी की है जालिम ये संसार

गरीबों का ना होता जग में यार

लाचारी कर दी है इनको मजबूर

निर्दयी दुनियां की यही है दस्तुर

खून पसीना कितना भी बहाया

दो जून की रोटी कभी खा ना पाया

ईमानदारी की जब चढ़ती है सुरूर

फीका पड़ जाता है चेहरे की नूर

रोम रोम में है संस्कार इनपे सवार

किसी पे ना करते दीन अत्याचार

फिर भी गरीबी बन आई है नासुर

कब होगा घर से आभाव दूर

पर्णकुटी में है देखा महल का सपना

सारा जग है इनका अपना ही अपना

इनके किस्मत का है सब ही कसुर

फिर क्यों बेबस बनी हँसी क्यूँ है क्रूर

पूजापात्रों में है देखा महल का सपना

सारा जग है इनका अपना ही अपना

इनके किस्मत का है सब ही कसुर

फिर क्यों बेबस बनी हँसी क्यूँ है क्रूर

संपादकीय

अल्पसंख्यकों की असुरथा से आतंकवाद तक पाक का यथार्थ



डॉ विजय गर्ग

लेखक

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया गया हालिया बयान केवल एक अतिशयोक्तिपूर्ण राजनीतिक टिप्पणी ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की उस मानसिकता का आईना है, जिसमें भारत के प्रति कटुता, अविश्वास, नफरत और वैचारिक विरोध आज भी गहरे पेटे हुए हैं। जरदारी ने ‘अखंड भारत’ की अवधारणा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन वे मुसलमान होने के नाते इससे सहमत नहीं हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में हिंदुओं के सुरक्षित और सुखी होने का दावा भी किया। सवाल यह है कि दुनिया किसी राष्ट्राध्यक्ष के दावे पर विश्वास करे या आंकड़ों और जमीन पर दिखाई देने वाली वास्तविकता पर? इतिहास का न्याय भावनाओं से नहीं, तथ्यों से होता है। और पाकिस्तान के संदर्भ में जनसांख्यिकी, अल्पसंख्यकों की स्थिति, धार्मिक स्वतंत्रता और आतंकवाद-ये चारों क्षेत्र ऐसे आईने हैं जिनमें उसकी अपनी तस्वीर साफ दिखाई देती है।

1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया एवं 1951 की जनगणना में पूरे तत्कालीन पाकिस्तान में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 14.6 प्रतिशत थी, पाकिस्तान की 2023 की आधिकारिक जनगणना में ‘हिंदू जाति’ की आबादी

3,867,729 और ‘अनुसूचित जाति’ की आबादी 1,349,487 दर्ज की गई है। कुल आबादी 240.46 मिलियन है। इन दोनों श्रेणियों को जोड़ें तो हिस्सा लगभग 2.17 प्रतिशत बैठता है। अर्थात् आज के पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की जनसंख्या हिस्सेदारी अत्यंत सीमित रह गई है। इसके विपरीत भारत की स्थिति को भी तथ्यों के साथ ही देखना चाहिए। भारत की अंतिम प्रकाशित पूर्ण जनगणना 2011 की है। उसमें मुस्लिम आबादी 14.23 प्रतिशत, यानी 17.22 करोड़ दर्ज हुई थी। यही वह बिंदु है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक अंतर सामने आता है। भारत ने धर्म के आधार पर नागरिकता की अवधारणा को राज्य की नागरिकता का आधार नहीं बनाया। संविधान ने हर नागरिक को समान नागरिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और अपनी आस्था के प्रति अधिकार आज भी गहरे पेटे हुए हैं। मुसलमानों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, सेना, शिक्षा, उद्योग, कला, खेल और प्रशासन सहित जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति है। इसके विपरीत पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की रिपोर्टें गंभीर प्रश्न उठाती हैं। ‘मन राइट्स वाच’ की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में ईशनिंदा कानूनों के दुरुपयोग ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, मनमाजी गिरफ्तारी और सामाजिक दबाव के प्रति अत्यंत संवेदनशील बना दिया है। रिपोर्ट में हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदियों सहित लगभग सभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और जबरन विवाह-धर्मांतरण जैसी समस्याओं का उल्लेख है। 2023 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जरनवाला में ईशनिंदा के आरोपों के बाद चर्चों और ईसाई घरो पर भीड़ के हमले हुए। ‘मन राइट्स वाच’ ने



पाकिस्तान में ईशनिंदा कानूनों के इस्तेमाल से अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर कब्जे और उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के मामलों का भी दस्तावेजीकरण किया है। ऐसे में जरदारी का यह कहना कि पाकिस्तान के हिंदू बहुत खुश हैं, एक झूठा, गुमराह करने वाला एवं भ्रामक राजनीतिक दावा तो हो सकता है, लेकिन उसे व्यापक तथ्यात्मक प्रमाण की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। किसी देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं या नहीं, इसका प्रमाण केवल राष्ट्राध्यक्ष का बयान नहीं, बल्कि उनके नागरिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, मंदिरों और पूजा स्थलों की सुरक्षा, कानून के सामने समानता तथा भयमुक्त जीवन है। भारत में सरकारों की खिलाफ मुसलमानों एवं अन्य अल्पसंख्यकों के द्वारा आवाज उठाई जा सकती है, न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। यही लोकतांत्रिक भारत और धार्मिक-सामुदायिक असुरक्षा से जुड़ते पाकिस्तान के बीच बुनियादी अंतर है। दूसरा बड़ा प्रश्न पाकिस्तान के भारत-विरोधी आतंकवाद का है। पिछले कई दशकों में सीमा पार आतंकवाद भारत की सुरक्षा के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में रहा है। संसद पर हमला, मुंबई हमले, पठानकोट, उरी, पुलवामा और जम्मू-कश्मीर में लगातार हिंसक घटनाएँ इस

समस्या का हिस्सा रही हैं। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर कार्रवाई की। विदेश मंत्रालय ने उस समय स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान की जमीन पर चल रहे आतंकवादी ढांचे के विरुद्ध कार्रवाई की गई क्योंकि पाकिस्तान उन्हें नष्ट करने के लिए पर्वाज कदम नहीं उठा रहा था।

2025 में पहलगाम के आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सुरक्षा नीति में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दिया। 22 अप्रैल 2025 के हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान-और पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत सरकार ने इसे आतंकवादी ढांचे के विरुद्ध लक्षित और नियंत्रित कार्रवाई बताया। यह परिवर्तन केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है। भारत ने आतंकवाद के साथ-साथ उसके वित्तीय और नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर भी ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने विदेशी तत्वों द्वारा नशीले पदार्थों को सीमा पार भेजकर ‘नाकों-टेर’ को वित्त उपलब्ध करने की बात कही है। यहां भारत की चुनौती केवल सीमा पार बंदूक लेकर खड़े आतंकवादी से नहीं है। चुनौती उस पूरे तंत्र से है जिसमें



बना दिया है, जहाँ एक टिप्पणी, तस्वीर या विचार विवाद खड़ा कर देता है। लोग दूसरों को गलत साबित करने में इतने उलझ गए हैं कि खुद को समझने का समय नहीं बचा। चेहरे पर सफलता की चमक है, लेकिन भीतर गहरी थकान छिपी है। प्रकृति मौन रहकर जीवन का गहरा सत्य सिखाती है, जिसे मनुष्य अपनी भागदौड़ में भूल चुका है। नदी कभी पहाड़ से टकराकर अपनी शक्ति नहीं दिखाती, फिर भी अपना रास्ता बना लेती है। हवा कभी पेड़ों से संघर्ष नहीं करती, फिर भी उसकी मौजूदगी महसूस होती है। प्रकृति बताती है कि हर बदलाव के लिए संघर्ष जरूरी नहीं, कई

बार धैर्य और निरंतरता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। लेकिन मनुष्य ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रतियोगिता में बदल दिया है। शिक्षा, रोजगार, रिश्ते और सामाजिक पहचान—हर जगह एक अदृश्य दौड़ चल रही है। इस दौड़ में ईंसान अक्सर भूल जाता है कि वह किस मंजिल के लिए इतना संघर्ष कर रहा है।



आर्थिक प्रतिफल इतना हो कि वह अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार की चिकित्सा और अपने बुढ़ोपे की सुरक्षा स्वयं कर सके। आज भी कृषि की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि किसान लागत का मालिक नहीं, लेकिन जोखिम का मालिक अवश्य बना दिया गया है। बीज महंगा है—किसान खरीदे। उाजल महंगा है—किसान भुगतान करे। मजदूरी बढ़ी—किसान दे। बिजली, सिंचाई, रकबाती, परिवहन और भंडारण—सबकी लागत किसान उठाए। लेकिन जब फसल बाजार में पहुँचे तो कीमत तय करना? अक्सर किसान नहीं। यही वह बिंदु है जहाँ किसान को खराब और बाजार की शक्ति आमने-सामने खड़ी दिखाई देती है। सरकारें MSP की घोषणा करती हैं, उत्पादन बढ़ने के आँकड़े प्रस्तुत करती हैं, कृषि बजट में वृद्धि बताती हैं और किसान कल्याण की योजनाओं की लंबी सूची गिनाती हैं।

सरकारी आँकड़ों के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजटीय प्रावधान 2013-14 के लगभग ₹21,934 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में लगभग ₹1.38 लाख करोड़ हुआ है तथा खाद्यान्न उत्पादन भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। लेकिन असली कसौटी बजट का आकार नहीं— किसान की आय और जीवन की सुरक्षा है। यदि उत्पादन बढ़ता रहे लेकिन उत्पादक आर्थिक रूप से असुरक्षित बना रहे, तो किसान का प्रश्न अधूरा है। यदि देश खाद्यान्न के मामले में मजबूत होता जाए लेकिन अनन्दाता अपनी अमली फसल के लिए कर्ज लेने को विवश रहे, तो व्यवस्था को अंतिम ताकत देने का आत्ममंथन करना चाहिए।

और यही वह स्थान है जहाँ सत्ता की नीतियों से सबसे तोखा सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या किसान नीति का केंद्र है या केवल नीति की भाषा का हिस्सा? चुनाव

वेलकम इंडिया 02

आतंकवाद, हथियार, ड्रोन, नशीले पदार्थ, फर्जी सूचनाएँ और सामाजिक विभाजन—सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिछले एक दशक से अधिक समय में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि उसने पाकिस्तान को यह संदेश दिया है कि आतंकवाद और बातचीत को समानांतर रास्तों पर नहीं चलाया जा सकता। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट कार्रवाई और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर अलग-अलग घटनाएँ जरूर हैं, लेकिन इनके पीछे एक समान संदेश दिखाई देता है—भारत अब आतंकवाद को केवल सहने या निंदा करने तक सीमित नहीं रहेगा। इस बदले हुए भारत की तस्वीर पाकिस्तान की बेचने को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता, अंतरिक्ष कार्यक्रम, रक्षा उत्पादन, डिजिटल बुनियादी ढांचा, वैश्विक कूटनीति और रणनीतिक प्रभाव लगातार बढ़े हैं। आज भारत को विश्व राजनीति में केवल दक्षिण एशिया की शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान की समस्या केवल यह नहीं है कि भारत उससे आर्थिक और सामरिक रूप से आगे निकल रहा है, उसकी बड़ी समस्या यह है कि भारत अपनी बहुलतावादी लोकतांत्रिक पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। जरदारी का बयान इसलिए भी विचारणीय है कि पाकिस्तान को भारत के भीर की विविधता पर टिप्पणी करने से पहले अपने घर के भीतर झाँकना चाहिए। भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ती आबादी का तथ्य स्वयं बताता है कि भारत में मुस्लिम समुदाय का अस्तित्व, विस्तार और सामाजिक जीवन किसी ‘समाप्ति’ की कहानी नहीं है। दूसरी ओर पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर आज भी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार

संस्थाएँ गंभीर चिंता व्यक्त कर रही हैं। इसलिए दुनिया के उन देशों को भी पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए, जो केवल रणनीतिक या राजनीतिक हितों के कारण उसकी हर बात का समर्थन करते हैं। किसी राष्ट्र का मूल्यांकन उसके भाषणों से नहीं, उसके व्यवहार से होना चाहिए। यदि कोई देश एक तरफ आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिबद्धता जताए और दूसरी तरफ उसकी धरती से सक्रिय आतंकी नेटवर्क लगातार पड़ोसी को निशाना बनाते रहें, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को केवल कूटनीतिक शब्दों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। भारत की शक्ति का अर्थ किसी धर्म या देश के प्रति घृणा नहीं, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई है। भारत के मुसलमान भी उनमें ही भारतीय हैं जितने हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और अन्य समुदाय। आज पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा प्रश्न भारत नहीं, बल्कि स्वयं पाकिस्तान है—वह कब यह स्वीकार करेगा कि आतंकवाद को विदेशी नीति का औजार बनाना अंततः उसी समाज को अस्थिर करता है जिसने उसे जन्म दिया? पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों की हिंसा का दंश स्वयं देश के नागरिक भी झेल रहे हैं। ‘मन राइट्स वाच’ के अनुसार 2025 में पाकिस्तान में विभिन्न उग्रवादी संगठनों के हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए। जरदारी को भारत के ‘अखंड भारत’ की चिंता करने से पहले अपने वर्तमान पाकिस्तान की अखंडता, शांति और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग्य यही है कि जो राष्ट्र भारत की एकता पर प्रश्न उठाता है, वह स्वयं आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और सामाजिक विभाजन से जूझता रहा है।

वेलकम इंडिया 02

मैं अब नहीं लड़ता क्योंकि मैंने खुद को खोकर जीतना छोड़ दिया है



प्रो. आरके जैन

लेखक

जब जीवन बहुत कुछ सिखा देता है, तब ईंसान हर आवाज का जवाब देना और हर लड़ाई लड़ना छोड़ देता है। वह कहता है—ह्रअब मैं नहीं लड़ता, ह्र तो दुनिया इसे उसकी कमजोरी समझ लेती है, जबकि यह अक्सर भीतर जागी हुई समझ का संकेत होता है। वह जान चुका होता है कि हर टकराव जरूरी नहीं और हर जीत की कीमत चुकाना समझदारी नहीं होती। कुछ विजय ऐसी होती हैं, जो बाहर तो जीत दिलाती हैं, लेकिन भीतर का सुकून छीन लेती हैं। ईंसान की सबसे बड़ी हार किसी संघर्ष से पीछे हटना नहीं, बल्कि उस दिन होती है जब वह अपने मन की शांति और

आत्मनिर्णय की शक्ति दूसरों और परिस्थितियों के हवाले कर देता है। आज का दौर शोर, विवाद और टकराव से भरा है। हर ओर बहसें, आरोप और विरोध की आवाजें हैं। समाचारों में विचारों की जगह संघर्ष दिखाता है, सोशल मीडिया पर संवाद की जगह कटुता बढ़ रही है और राजनीति में समाधान से अधिक टकराव है। हर ईंसान किसी न किसी लड़ाई में उलझा है—कोई रोजगार के लिए, कोई महंगाई से, तो कोई पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन इन लगातार लड़ाइयों ने ईंसान की भीतर की शांति को कितना कमजोर किया है, इस पर ध्यान कम दिया जाता है। क्योंकि हर समय संघर्ष में रहने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे अपना हँसी, सहजता और मानसिक शांति खो देता है।

आज संघर्ष का मैदान केवल बाहर नहीं, ईंसान के घर और मन तक पहुँच चुका है। हर कोई किसी न किसी अदृश्य लड़ाई से गुजर रहा है—कोई पिता जिम्मेदारियों के बोझ में दबा है, कोई युवा सफलता की दौड़ में अपनी खुशियाँ खो रहा है और कोई कर्मचारी खुद को साबित करने की जितनी भी खी है, तब भी सोशल मीडिया ने बिना मैदान के भी हर व्यक्ति को योद्धा

वाह रे प्रजापालक: लुटेरों को वरदानों की सौगात, अन्नदाता पर दरिद्रता की बरसात?



एनके शर्मा

लेखक

जिस देश में अन्न को ब्रह्म कहा गया, जिस सभ्यता ने किसान को ‘अन्नदाता’ कहकर उसको श्रम को देवत्व प्रदान किया, उसी देश में आज सबसे असहज कर देने वाला प्रश्न यही है— जो व्यक्ति पूरे राष्ट्र का पेट भरता है, उसका अपना पेट अधूरा क्यों है? यह प्रश्न किसी एक दल, किसी एक सरकार या किसी एक नेता के विरुद्ध राजनीतिक नारा नहीं है। यह उस शासन-व्यवस्था के चरित्र पर सवाल है, जो किसान के कंधे पर राष्ट्र की खाद्य-सुरक्षा का भार रखकर उसके हाथ में आर्थिक असुरक्षा थमा देती है। सत्ता के शिखरों पर बैठे माननीयों के लिए वेतन, भत्ते, आवास, यात्रा, सुरक्षा, चिकित्सा और अन्य संस्थागत सुविधाओं की व्यवस्था होती है। उच्च प्रशासनिक वर्ग के लिए पद के अनुरूप संसाधन और सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। पूँजी के लिए नीतियाँ, ऋण, निवेश, बाजार और प्रोत्साहन की पूरी आर्थिक भाषा मौजूद है। बड़े कारोबार के लिए

जोखिम कम करने के रास्ते खोजे जाते हैं। लेकिन किसान? उसके हिस्से में मौसम का जोखिम, बाजार का जोखिम, कर्ज का जोखिम, लागत का जोखिम, बीमारी का जोखिम और फसल नष्ट होने का जोखिम—सब कुछ है। उसके पास न महँगे कर्कीलों की फौज है, न नीति-निर्माताओं तक पहुँच रखने वाली प्रभावशाली लॉबी, न बाजार की कीमत तय करने की ताकत। फिर भी उससे अपेक्षा है कि वह देश को अन्न देता रहे।

यह कैसा आर्थिक न्याय है? सरकार की PM-KISAN योजना पात्र किसान परिवारों को ₹6,000 सालाना आय बचावता देती है, तीन सामान किस्तों में। यह सहायता निश्चित रूप से उपयोगी है; लेकिन स्वयं सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कृषि क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन, स्थिर आय और सामाजिक सुरक्षा अभी भी नीति की महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। सवाल यह नहीं कि किसान को ₹6,000 क्यों दिया जाए। सवाल यह है कि किसान की आर्थिक संरचना ऐसी क्यों नहीं बनाई गई कि उस सम्मानजनक जीवन के लिए इतनी छोटी सहायता पर निर्भर न रहना पड़े? गरीबी पर मरहम लगाना और गरीबी पैदा करने वाली व्यवस्था को बदलना—दो अलग बातें हैं।

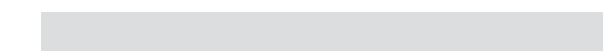
किसान को खराब नहीं चाहिए। उसे ऐसी कृषि-अर्थव्यवस्था चाहिए जिसमें उसकी लागत सुरक्षित हो, उत्पादन का उचित मूल्य सुनिश्चित हो, भुगतान समय पर मिले, फसल नष्ट होने पर वास्तविक क्षतिपूर्ति मिले और उसकी मेहनत का



आर्थिक प्रतिफल इतना हो कि वह अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार की चिकित्सा और अपने बुढ़ोपे की सुरक्षा स्वयं कर सके। आज भी कृषि की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि किसान लागत का मालिक नहीं, लेकिन जोखिम का मालिक अवश्य बना दिया गया है। बीज महंगा है—किसान खरीदे। खाद महँगी है—किसान खरीदे। डीजल महँगा है—किसान भुगतान करे। मजदूरी बढ़ी—किसान दे। बिजली, सिंचाई, रकबाती, परिवहन और भंडारण—सबकी लागत किसान उठाए। लेकिन जब फसल बाजार में पहुँचे तो कीमत तय करना? अक्सर किसान नहीं। यही वह बिंदु है जहाँ

किसान को खराब और बाजार की शक्ति आमने-सामने खड़ी दिखाई देती है। सरकारें MSP की घोषणा करती हैं, उत्पादन बढ़ने के आँकड़े प्रस्तुत करती हैं, कृषि बजट में वृद्धि बताती हैं और किसान कल्याण की योजनाओं की लंबी सूची गिनाती हैं।

सरकारी आँकड़ों के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजटीय प्रावधान 2013-14 के लगभग ₹21,934 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में लगभग ₹1.38 लाख करोड़ हुआ है तथा खाद्यान्न उत्पादन भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।



आते हैं तो किसान ‘अन्नदाता’ हो जाता है। घोषणाएँ होती हैं तो वह ‘देश की रीढ़’ बन जाता है। बजट आता है तो उसके नाम पर योजनाएँ गिनाई जाती हैं। लेकिन जब वह अपनी उपज के उचित मूल्य, कर्ज, बीमा, लागत और वास्तविक आय की बात करता है, तब वह अचानक फाइल, प्रक्रिया, समिति और निर्णयों के बीच खो जाता है। यह विरोधाभास लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। किसान को लगातार यह समझाया जाता है कि वह राष्ट्र की सेवा कर रहा है।

लेकिन क्या राष्ट्र भी किसान की सेवा करने को तैयार है? यदि कोई सैनिक सीमा पर खड़ा होकर राष्ट्र की रक्षा करता है तो राष्ट्र उसके लिए सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक संरक्षण को अपना दायित्व मानता है। फिर खेत की सीमा पर मौसम, बाजार का अंतिम ताकत और किसान तक पहुँचाना ही असली शासन है। यहाँ हमारी व्यवस्था बार-बार कठपंते में खड़ी होती है। कागज पर किसान सशक्त है। विज्ञापन में किसान समृद्ध है। भाषण में किसान सम्मानित है। लेकिन खेत में? वह आज

भी आसमान देखकर मौसम का अनुमान लगाता है और मंडी देखकर अपनी किस्मत। यह विडम्बना जितनी आर्थिक है, उससे कहीं अधिक नैतिक है। क्योंकि किसान केवल एक उत्पादक नहीं है। वह खाद्य सुरक्षा का आधार है।

उसके श्रम से शहर चलते हैं, उद्योगों की खाद्य-श्रृंखला चलती है, स्कूलों और अस्पतालों तक भोजन पहुँचता है और करोड़ों परिवारों की रसेाई जलती है। सरकारी आँकड़ों में कृषि परिवारों की औसत आय में वृद्धि के संकेत अवश्य मिलते हैं; उअइअफ्रक के सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय ₹13,661 बताई गई थी। लेकिन उसी व्यापक ग्रामीण वास्तविकता में खेती की लागत, उपभोग व्यय, ऋण और अन्य खर्च के स्रोतों की विविधता को भी समझना आवश्यक है। अतः केवल औसत आय का आंकड़ा प्रस्तुत करके किसान की वास्तविक समृद्धि को छिपा कर देना भी अधूरा निष्कर्ष होगा। किसान की समृद्धि का पैमाना उसके बैग खाले में आने वाली किसी एक किस्त से नहीं, बल्कि पूरे वर्ष के अंत में उसके पास बची हुई आर्थिक सुरक्षा से तय होना चाहिए। और यही वह प्रश्न है जिससे सत्ता और असहज होती है। क्योंकि यदि किसान को सचमुच आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया गया, तो उसे हर चुनाव में राहत, अनुदान और घोषणा के नाम पर आवश्यक बनने की जरूरत कम हो जाएगी।



पारंपरिक खेलों के साथ एडवेंचर और आइस स्पोर्ट्स को बढ़ावा: मुख्यमंत्री

एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का शुभारंभ, उत्तराखंड को अंतरराष्ट्रीय खेल केंद्र बनाने पर जोर

वेलकम इंडिया संवाददाता

देहरादून। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता 20 अगस्त तक चलेगी। आयोजन में देश-विदेश से खिलाड़ी, प्रशिक्षक और तकनीकी अधिकारी प्रतिभाग कर रहे हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों का उत्तराखंड में स्वागत करते हुए सभी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए यह गौरव का विषय है कि प्रदेश को एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर



मिला है। इससे उत्तराखंड की पहचान शीतकालीन और आइस स्पोर्ट्स के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अनुकूल गंतव्य के रूप में और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने आयोजन से जुड़े आयोजकों, प्रशिक्षकों, तकनीकी अधिकारियों और सहयोगियों को

प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया गया, जिसके माध्यम

से आधुनिक एवं विश्वस्तरीय खेल अवस्थापना का मजबूत आधार तैयार हुआ। इसी का परिणाम है कि उत्तराखंड अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने में सक्षम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू



करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसके तहत आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी, जहां खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधाएं मिलेंगी। हल्द्वानी में प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य

भी तेजी से चल रहा है, जबकि लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य की नई खेल नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में अवसर दिए जा रहें हैं। प्रतिभावान



खिलाड़ियों को खेल छत्रवृत्ति के साथ आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उद्योगपन खिलाड़ी योजना

और खेल किट योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक खेलों के साथ-साथ वॉटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स और आइस स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए पसंदीदा खेल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित हो। इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, एशियन स्केटिंग यूनियन के अध्यक्ष म्यांग ही चांग, आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अमिताभ शर्मा, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, निदेशक खेल दीपति सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक एवं अपर जिलाधिकारी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस पर तहसील मेंहदावल में सुनी जनता की समस्याएं, दिए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश



वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। सोमवार को पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना एवं अपर जिलाधिकारी ने तहसील मेंहदावल में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर जनसामान्य की समस्याओं एवं शिकायतों को सुना गया। इस दौरान पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में

फरियादियों की शिकायतों को मौके पर सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक शिकायत का मौके पर जाकर निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। पुलिस एवं राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण में आपसी समन्वय एवं सामंजस्य बनाए रखते हुए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को स्पष्ट

निर्देशित किया गया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। तत्पश्चात अधिकारियों द्वारा शिकायत पंजिका का निरीक्षण कर पूर्व में निस्तारित शिकायतों के संबंध में फीडबैक भी लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर राजस्व एवं पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। खलीलाबाद तहसील क्षेत्र के सेमरियावां विकासखंड की दुधारा और परसाशेख न्याय पंचायतों में रविवार को 'इग मुक्त जन अभियान' के तहत जागरूकता बैठक आयोजित की गई। चंद्रा शिक्षण संस्थान में प्रगति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व अभियान के राष्ट्रीय संयोजक एवं यूथ आइकन अवाडी प्रदीप सिसोदिया ने किया। कार्यक्रम में दो सौ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। बैठक में दुधारा न्याय पंचायत के कोहरियावा, जोतडीह, दुबौलिया, पिपरा गोविंद, मदारपुर, घुसुरा और दरियाबाद तथा परसाशेख न्याय पंचायत के अहिरौली, छंगुलिया बगुलिया, दिघवा, मुहम्मदगढ़, परसाशेख और सिसवा दाखिल सहित विभिन्न क्षेत्रों के



लोग शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रदीप सिसोदिया ने कहा कि कम उम्र के युवा और युवतियां तेजी से नशे के जाल में फंस रहे हैं। युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी है और इसे नशे से बचाना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। प्रदीप सिसोदिया ने कहा कि जब परिवार का मुखिया नशे की हालत में घर पहुंचता है तो घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है और इसका सीधा प्रभाव बच्चों के मानसिक एवं

सामाजिक विकास पर पड़ता है। नशे के कारण घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाओं और चोरी जैसी घटनाओं में भी वृद्धि की चिंता जताई गई। उन्होंने कहा कि नशे की लत के कारण कई परिवारों की संपत्ति बिक गई और बच्चों की पढ़ाई तथा बेटियों के विवाह तक प्रभावित हुए हैं। कॉलेजों के आसपास, चाय की दुकानों, रेस्टोरेंट और अन्य स्थानों पर नशे के प्रसार को रोकने के लिए समाज और प्रशासन को मिलकर काम करने

की जरूरत है। कार्यक्रम के समापन पर चंद्रा शिक्षण सेवा संस्थान की शिक्षिका संजना ने उपस्थित लोगों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। लोगों ने किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहने, परिवार और परिचितों को नशे से बचाने तथा स्वस्थ और नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। प्रदीप सिसोदिया के आह्वान पर लोगों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर 'हमें गर्व है कि मेरा परिवार नशामुक्त है' का स्टीकर लगाने का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम में 'नशा छोड़ें, जीवन जोड़ें' का संदेश प्रमुखता से दिया गया। कार्यक्रम में रमा शंकर यादव, संजय कुमार सिंह, देवेंद्र सिंह, राम जियातान सिंह, लक्की सिंह, मो. सलमान, मो. हसन, चंद्र भूषण सिंह, प्रसिद्ध पाल, अनिल चौहान, सीताराम, अब्दुल मुरद, हीरा लाल मोर्य, शम्सुद्दीन, राघवेंद्र प्रताप सिंह, कमालुद्दीन, चंद्रभान त्रिपाठी, मो. आरिफ, हैदर हुसैन, नीरज

सिंह, नागेंद्र चौहान, अमन, अनीश, मो. शामी, मो. हजरत अली, शैलेंद्र सिंह, गंगा प्रसाद, विजय कुमार, नसीबुल्लाह, शिवलाल गुप्ता, पवन गुप्ता, चंदन, सूरज, विक्रम, अमित चौहान, चंदन मोर्य, रमेश चंद्र, दिनेश यादव, परशुराम, शुभम सिंह, रवि, कमाल, रामजीत, शमसुल हक, मो. हनीफ, गौतम, आयुष तिवारी, सिंपू सिंह, बोला प्रसाद, राम लखन, अनीता, रोहनी, सपना, नेहा कुमारी, संगीता, शुभवती, सुमन, पवन, अभिषेक, धनंजय सिंह, रामशरण, देवेंद्र सिंह, अब्दुल्ला, चंद्रमणि त्रिपाठी, इकराम, राजिम, फैयाज और कृपाशंकर त्रिपाठी सहित दर्जनों लोगों ने अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने समाज में बढ़ते नशे को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए अभियान की सराहना की। उन्होंने प्रदीप सिसोदिया को अभियान में हरसंभव सहयोग देने और इसे लगातार जारी रखने का भरपूर आशीर्वाद दिया।

पीपलकोटी टनल हादसा: लापता श्रमिकों की तलाश में रेस्क्यू अभियान तेज करने के निर्देश

वेलकम इंडिया संवाददाता

देहरादून। पीपलकोटी में टीएचडीसी की निमाणांधीन टनल में हुए हादसे को लेकर आयुक्त गढ़वाल मंडल आनन्द स्वरूप ने जिला सभागार गोपेश्वर में समीक्षा बैठक की। बैठक में रेस्क्यू अभियान की प्रगति, उपलब्ध संसाधनों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और श्रमिकों से जुड़े विषयों की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में कुल 22 श्रमिक प्रभावित हुए हैं। इनमें से 12 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सात श्रमिक जिला अस्पताल गोपेश्वर में उपचाराधीन हैं, जबकि एक श्रमिक का उपचार एम्स त्रिप्रेश्वर में चल रहा है। हादसे में आठ श्रमिकों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि दो श्रमिक अभी भी लापता हैं। उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। आयुक्त आनन्द स्वरूप ने निर्देश दिए कि टनल में लापता श्रमिकों की तलाश

और बचाव कार्य पूरी गंभीरता और तेजी के साथ जारी रखा जाए। उन्होंने रेस्क्यू अभियान में लगी सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि रेस्क्यू अभियान के दौरान टनल से तीन मशीनों हटाई जा चुकी हैं। एक एक्सकेवेटर और एक डम्पर को हटाने का कार्य अभी जारी है। आयुक्त ने शेष मशीनों को जल्द हटाकर टनल के भीतर खोज एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आरबीएनएल के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर टीएचडीसी से संबंधित रेस्क्यू और अन्य आवश्यक कार्यों में सहयोग सुनिश्चित करने को कहा। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए रेस्क्यू अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। बैठक में श्रमिकों के हितों से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई।

15 अगस्त को धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

वेलकम इंडिया संवाददाता

मथुरा/गोवर्धन। क्षेत्र के आदर्श शिक्षा निकेतन गर्ल्स इंटर कॉलेज में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रबंधक दान बिहारी शर्मा द्वारा ध्वजारोहण करके तिरंगे को सलामी दी गई, इसके उपरांत सभी ने श्री राम सभागार में अपना-अपना स्थान ग्रहण किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला शुरू हुई। इस अवसर पर छात्रछात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर समाबंध दिया और दर्शकों का मन मोह लिया। नन्हे छात्रों द्वारा पेड़ों के संरक्षण पर एक नाटक की प्रस्तुति दी, वहीं चौथी कक्षा के छात्र-छात्राओं द्वारा मेरा गाथा गंधो का लीडर गाने पर प्रस्तुति दी गई जिस पर दर्शकों ने हंसते हंसते पेट पकड़ लिया। कार्यक्रम में छात्रा बिशाखा द्वारा बंगाली नृत्य प्रस्तुत किया गया इसके उपरांत छात्रा अंबिका, दिव्यांशी राधाविनोदिनी, छवि एवं एकता द्वारा भाषण दिया गया। सभी ने एक जिम्मेदार नागरिक बनने की लोगों से अपील की एवं अपने देश



को शिखर तक पहुंचाने के लिए शपथ दिलवाई। कार्यक्रम के अंत में पिछले सत्र में वार्षिक परीक्षा में अक्वल आने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया जिसमें कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं की टॉपर कीर्ति एवं कक्षा 10 की बोर्ड का परीक्षाओं की टॉपर विशाखा दास अग्रणी रही। कार्यक्रम को समाप्ति

पर छात्र-छात्राओं को प्रधानाचार्य श्रीमती पूर्णिमा कौशिक द्वारा सभी को एक अच्छे भारतीय दिए बनने की सलाह दी। इस अवसर पर विद्यालय के उप प्रबंधक वन बिहारी भारद्वाज, अभिभावक गण एवं विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। बच्चों ने कार्यक्रम के उपरांत मिठाई खाकर राष्ट्रीय पर्व का आनंद लिया।

अडींग चौकी पुलिस के सराहनीय कार्यों को मिला सम्मान, गम्बर सैनी ने तिरंगा दुपट्टा पहनाकर पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित



वेलकम इंडिया संवाददाता

मथुरा/गोवर्धन। थाना गोवर्धन क्षेत्र की अडींग चौकी पुलिस द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे सराहनीय कार्यों और बेहतर पुलिसिंग को देखते हुए सोमवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाजसेवी गुलाब सिंह उर्फ गम्बर सैनी ने चौकी प्रभारी प्रदीप भदौरिया सहित समस्त पुलिस टीम का स्वागत एवं सम्मान किया। सम्मान समारोह के दौरान समाजसेवी गुलाब सिंह उर्फ गम्बर सैनी ने चौकी प्रभारी प्रदीप

भदौरिया, हेड कांस्टेबल मानवेन्द्र सिंह, विजय कुमार, सत्येंद्र कुमार, कांस्टेबल अमित कुमार, राम सुंदर, वीरेंद्र यादव, देवेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों को तिरंगा दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही देश की महान विभूतियों के स्मृति चित्र भेंट कर पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर गम्बर सैनी ने कहा कि पुलिसकर्मी दिन-रात अपनी ड्यूटी निभाते हुए समाज की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अडींग

चौकी पुलिस द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने तथा आमजन की सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं। ऐसे सम्मान से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। समारोह के दौरान पुलिसकर्मियों ने समाजसेवी गुलाब सिंह उर्फ गम्बर सैनी का आभार व्यक्त किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हुए इस सम्मान समारोह ने पुलिस और आमजन के बीच बेहतर संबंधों एवं आपसी सहयोग का संदेश दिया।

पत्रकार हितों की रक्षा के लिए एकजुट हुआ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब, पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

उत्पीड़न और फर्जी मुकदमों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान, कांटे चौकी प्रकरण को लेकर एसपी को सौंपेंगे ज्ञापन

वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा, अधिकारों और हितों की रक्षा को लेकर रविवार को खलीलाबाद के एक निजी होटल में जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के बैनर तले पत्रकारों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे वरिष्ठ एवं युवा पत्रकारों ने पत्रकारों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न, अभद्रता, मारपीट और फर्जी मुकदमों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। पत्रकारों ने एकजुट होकर स्पष्ट किया कि अब किसी भी पत्रकार के साथ अन्याय हुआ तो संगठन मजबूती से उसके साथ खड़ा होगा। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की जिला एवं तहसील इकाइयों में पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। शैलेंद्र मणि त्रिपाठी को संयोजक और बाबुल

श्रीवास्तव को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर सदरे आलम खान और जितेंद्र पाठक को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी क्रम में रितेश उपाध्याय, विजय गुप्ता और हरिओम चौधरी को उपाध्यक्ष, मिथिलेश कुमार धुरिया को उपाध्यक्ष, विजय मिश्रा को संगठन सचिव तथा केदारनाथ दुबे को संयुक्त सचिव बनाया गया। अंशु सिंह को सचिव, कल्याण भट्ट को प्रवक्ता, कौशल किशोर को जिला उप सचिव की जिम्मेदारी दी गई।

संगठन में नवनीत श्रीवास्तव और संजय श्रीवास्तव को सचिव, विपिन राय को कोषाध्यक्ष, राजेश्वर को मीडिया प्रभारी तथा सतीश पांडे को संगठन ऑडिटर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तहसील स्तर पर भी संगठन को विस्तार देते हुए मेहदावल तहसील अध्यक्ष, की जम्मेदारी सुनील श्रीवास्तव, खलीलाबाद तहसील



अध्यक्ष मोहन राजभर, खलीलाबाद तहसील उपाध्यक्ष अनिल मोर्य तथा तहसील महासचिव गणेश चौरसिया को बनाया गया। बैठक में पत्रकारों ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज की समस्याओं को सामने लाने का कार्य करते हैं। ऐसे में पत्रकारों के साथ अमानवीय व्यवहार, दबाव, धमकी, मारपीट या कथित फर्जी

मुकदमे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। पत्रकारों ने कहा कि शासन स्तर से पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद यदि जिले में किसी पत्रकार का उत्पीड़न होता है तो इसे चुपचाप स्वीकार नहीं किया जाएगा। जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पत्रकार हितों के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज

बुलंद करेगा। बैठक में कोतवाली क्षेत्र के कांटे स्थित चौकी के पास पत्रकार के साथ कथित मारपीट तथा बाद में कोतवाली में पत्रकार के साथ कथित अभद्रता का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया। पत्रकारों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। निर्णय लिया गया कि जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नेतृत्व में पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेगा। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग के साथ ही दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी को भी पत्र सौंपा जाएगा। जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष बाबुल श्रीवास्तव ने कहा कि पत्रकार अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी संगठन से जुड़े रहें, लेकिन संतकबीरनगर जिले में जब भी किसी पत्रकार के साथ उत्पीड़न या अन्याय

होगा, जर्नलिस्ट प्रेस क्लब उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के हक और अधिकारों के प्रबंध निदेशक डॉ. शाहरुख अहमद सिद्दीकी की पुत्री माहिरा सिद्दीकी ने कम उम्र में कुरआन शरीफ मुकम्मल कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। माहिरा की इस उपलब्धि पर परिवार और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। माहिरा सिद्दीकी की मां तरनुम सिद्दीकी भी चिकित्सक हैं। परिवारों के अनुसार माहिरा ने मेहनत और लगन के साथ कुरआन शरीफ की तिलावत पूरी की। इस उपलब्धि को परिवार के लिए खुशी और गर्व का अवसर बताया गया है। माहिरा सिद्दीकी के कुरआन शरीफ मुकम्मल करने पर क्षेत्र के लोगों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। पूर्व प्रमुख मशहूर आलम चौधरी, जिला कग्रिस कमेटी के उपाध्यक्ष सैयद तारिक हुसैन, जिला सचिव अलीक सिद्दीकी, सोशल मीडिया विभाग के

माहिरा सिद्दीकी ने कम उम्र में मुकम्मल किया कुरआन शरीफ, बधाइयों का तांता

वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। सेमरियावां स्थित लाइफ लाइन हॉस्पिटल एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर के प्रबंध निदेशक डॉ. शाहरुख अहमद सिद्दीकी की पुत्री माहिरा सिद्दीकी ने कम उम्र में कुरआन शरीफ मुकम्मल कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। माहिरा की इस उपलब्धि पर परिवार और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। माहिरा सिद्दीकी की मां तरनुम सिद्दीकी भी चिकित्सक हैं। परिवारों के अनुसार माहिरा ने मेहनत और लगन के साथ कुरआन शरीफ की तिलावत पूरी की। इस उपलब्धि को परिवार के लिए खुशी और गर्व का अवसर बताया गया है। माहिरा सिद्दीकी के कुरआन शरीफ मुकम्मल करने पर क्षेत्र के लोगों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। पूर्व प्रमुख मशहूर आलम चौधरी, जिला कग्रिस कमेटी के उपाध्यक्ष सैयद तारिक हुसैन, जिला सचिव अलीक सिद्दीकी, सोशल मीडिया विभाग के



जिलाध्यक्ष मुहम्मद परवेज अख्तर, अखलाक अहमद चौधरी, मोहम्मद सलमान, अख्तर हुसैन, अतहरुल बारी, मुहम्मद अफजल, मुहम्मद अकरम नजीर, अबुल कलाम, महेश कुमार, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद तत्व्य, अतीकुर्रहमान, मौलाना सेराज अहमद, रियाज अहमद सहित अन्य लोगों ने बधाई देते हुए खुशी का इजहार किया। लोगों ने कहा कि कम उम्र में कुरआन शरीफ मुकम्मल करना माहिरा की मेहनत, लगन और धार्मिक शिक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने माहिरा के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए परिवार को भी इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दीं।

